

प्रादेशिक समाचार
दिनांक-20.09.2024 (दोपहर-1455 बजे)

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज रांची के नामकुम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद – आईसीएआर और राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान –एनआईएसए के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आईसीएआर और एनआईएसए ने देश में लाख कीट का उत्पादन हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि सप्लाई चेन, बाजार की व्यवस्था करने से किसानों को बेहतर मूल्य मिल सकता है।

इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ तथा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज शिल्पकारों से अपील की कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाकर उद्यमी और व्यापारी बनें। श्री मोदी महाराष्ट्र में वर्धा के स्वावलम्बी मैदान में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की वर्षगांठ पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे।

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज साहिबगंज के भोगनाडीह से भाजपा की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर साहिबगंज के पुलिस लाइन मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य की भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकना भाजपा की प्राथमिकता है। केन्द्रीय मंत्री ने बांग्लादेशी घुसपैठ का जिक्र करते हुए कहा कि इस समस्या का समाधान भाजपा ही कर सकती है।

इससे पहले केन्द्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में अपने आवास पर छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा से पीड़ित लगभग 55 लोगों के साथ बातचीत करते हुए कहा है कि सरकार ने मार्च 2026 से पहले देश से नक्सलवाद की विचारधारा और नक्सलवाद को समूल नष्ट करने का निर्णय लिया है। श्री शाह ने नक्सल समूहों से हथियार और हिंसा का रास्ता छोड़ कर आत्मसमर्पण करने का आग्रह भी किया।

दुमका जिले में झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता—

झारखंड हाईकोर्ट में राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में आज सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई। इसके बाद अदालत ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वर्चुअल माध्यम से अपनी दलील पेश की। सिब्बल ने कहा कि केंद्र सरकार ने बांग्लादेश घुसपैठियों के झारखंड में प्रवेश के संबंध में कोई डाटा अपने शपथ पत्र में नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता इस जनहित याचिका को पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि, झारखंड में कुछ माह में विधानसभा चुनाव होने हैं।

*****समाप्त*****